SHRI BIRENDRA SINGH RAO: Sir, I can give an assurance that these programmes will be implemented seriously, concientiously and efficiently. But achievement of target does not depend upon human beings.

PROF. MADHU DANDAVATE: Sir, what does he mean by saying "does not depend upon human beings" alone.

SHRI BIRENDRA SINGH RAO: Yes, God has greater part to play in agriculture.

PROF. MADHU DANDAVATE: Then you hand over the Government to God.

समस्यामूलक गांवों का हल

*83. **श्री विरधी चन्द जैन** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में, जिसमें देश के मरूस्थल का 40 प्रतिशत भाग है और जिसके सामने पेयजल की गम्भीर समस्या है, गावों को समस्यामूल के रूप मे निर्धारित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अपनाई गई कसौटी को न माने जाने के कारण बहुत कम गांवों को समस्यामूलक गाव घोषित किया गया है ;

(ख) क्या राजस्थान सरकार ने अनेक बार यह बात सम्बद्ध अधिकारियो के ध्यान में लाई है परन्तु वह इसे मानने को तैयार नही है , और

(ग) क्या सरकार का विचार इस बारे मे तत्काल कार्यवाही करने और राज्य सरकार एवं जनता की न्यायोचित माग को स्वीकार करने तथा पेयजल की उनकी गम्भीर समस्या को हल करने मे सहायता करने का है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी): (क) तथा (ख) 1972 में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार राजस्थान में 4277 ग्रामों को "समस्याग्रस्त ग्राम" पाया गया था। तत्पश्चात् राजस्थान सरकार ने यह अध्यावेदन किया कि समस्याग्रस्त ग्रामों की संख्या 4277 से अपेक्षाकृत अधिक है। केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम का उद्देश्य 1972 में पाये गए केवल समस्याग्रस्त ग्रामों को ही शीघ्रातिशीघ्र इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाना है । तथापि, राजस्थान सरकार द्वारा बाद में बताई गई अधिक संख्या विवादग्रस्त है । राज्य सरकार के अनुरोध पर राजस्थान सरकार के परामर्श से सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा जो अधिक संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(ग) राज्य सरकार, यदि चाहे तो वह स्वय राज्य की संशोधित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की सहायता से ऐसे ग्रामों में जलपूर्ति योजनाओं का काम अपने हाथ में ले सकती है जो 1972 की सूची में नही है लेकिन समस्याग्रस्त ग्राम की कसौटी पर खरे उतरते हैं और इस प्रकार इन ग्रामों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है।

श्री विरधी चन्द जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि सेन्ट्रली सांन्सर्ड प्रोग्राम आफ एक्सीलरेटेड रुरल वाटर सप्लाई के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने सन् 1972 में समस्याग्रस्त गावो को सम्मिलित करने के लिए कौन से आधार या क्राइटीरिया तय किया और उसके लिए कितनी राशि 1979-80 मे निर्धारित की है तथा राजस्थान सरकार को कितनी राशि उपलब्धा हुई है ?

मेरा दूसरा प्रश्न है कि रिवाइज्ड मिनिमम नीड्स प्रोग्राम के अन्तर्गत कितने फन्ड्स किन किन प्रांतों को एलाट किए हैं–मैं विशेष तौर से राजस्थान के बारे मे जानना चाहता हू साथ ही राजस्थान सरकार ने अभ्यावेदन के द्वारा कितने ग्राम समस्यामूलक बताए है ?

मेरा एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि राजस्थान सरकार ने केन्द्र सरकार के बताए हुए क्राइटीरिया के आधार पर गावो की सूची भेजी है लेकिन आपके विभाग के अधिकारी सही स्थिति को मानने के लिए तैयार नही है अतः क्या आप केन्द्र एवं राज्य के अधिकारियों की बैठक बुलाकर सही ग्राम सूची तैयार करने मे सहयोग देने के लिए तैयार है ?

SHRI P. C. SETHI: Sir, I have committed a mistake of not noting down the number of questions he has put. But I will try to answer them. Sir, the allocation under the A.R.P. in 1977-78 was Rs. 40 crores out of which Rajasthan got Rs. 252.32 lakhs. Under Minimum Needs Programme, it was Rs. 78.0 lakhs out of which Rajasthan got Rs. 703.0 lakhs. For 1978-79, it was Rs. 60.0 crores, out of which Rajasthan got Rs. 352.27 lakhs and under Minimum Needs Programmes the allocation was Rs. 114.0 crores out of which Rajasthan got Rs. 9.2 crores. For 1979-80, Rs. 60.0 crores is the total allocation which is being finalised and the allocation under Minimum Needs Programme is round about Rs. 150.0

crores out of which Rajasthan is likely to get about Rs. 10.0 crores.

एक प्रश्न माननीय सदस्य ने यह पूछा था कि राजस्थान सरकार ने कितने समस्यामूलक गांवों की सूची भेजी तो 1972 में जो सर्वेक्षण हुआ था उसके मुताबिक 4277 समस्यामूलक गांव थे, वही स्वीकार किए गए और उसी के अनुसार फंड्स निर्धारित थे। लेकिन बाद में राजस्थान सरकार ने दो सूचियां भेजी—एक में सचिव ने 1978 में लिखा कि लगभग बीस हजार गांव समस्यामूलक हैं और फिर कुछ दिन बाद दूसरा पत्र आया जिसमें लिखा कि बीस हजार नहीं, 24 हजार हैं। इसलिए मैंने मूल प्रश्न के उत्तर में कहा है कि विवादग्रस्त मसला है। यह बात नहीं है कि आपकी सूची स्वीकार करने का प्रश्न है या नहीं। इसमें कोई शक नही है कि जितने भी समस्यमूलक गांव हैं, वे निपटाने हैं। तो ऐसा समझने का कोई कारण नही है कि अफसर आपकी बात को मानेंगे या नही मानेंगे आज नहीं मानेंगे तो कल मानेंगे। सवाल यह कि वास्तव म जो संख्या आपने भेजी है वह सही है या नहीं है, उसका निर्धारण करना है। कभी कभी जब सकेयरसिटी होती है, तो डिमाण्ड इन्पलेटेड भी हो जाती है।

श्री बिरधी चन्द जैन : इसलिए मैंने सुझाव दिया है कि आप अपने अधिकारियों और राजस्थान के अधिकारियों की बैठक बुलाकर इस मसले को जल्दी से जल्दी हल करा दीजिए और मै जानना चाहता हूं कि आप कब तक इन समस्यामूलक गांवों की समस्याएं हल कर सकेंगे?

श्री प्रकाश चन्द सेठी : मुझे मीटिंग बुलाने में कोई एतराज नही है, आप कहें तो मीटिंग परसों बुलाई जा सकती है। लेकिन सवाल यह है कि मीटिंग बुलाने से काम नही चलेगा, इसमें सैंसस करने की आवश्यकता है। दुर्भाग्य से हमारे पास ऐसी कोई मशीनरी नही है जो समस्या मूलक गांवों का सैंसस कर सके, वह तो राजस्थान सरकार ही करेगी और अल्टीमेटली जो वे कहेंगे, वही निश्चय होगा, इसलिए मीटिंग बुलाने से कोई फायदा नही है। हम 4277 कहेगे और आप 20 हजार या 24 हजार कहेंगे, 28 हजार भी आप कह सकते हैं। हमें समस्यामूलक गांवों को पानी देना है।

SHRI A. T. PATIL: Will the Central Government in cooperation with the State Government of Rajasthan undertake a phased time-bound programme to provide drinking water to all the villages in Rajasthan and whether such a phased time-bound programme will be undertaken in respect of all the villages in other States?

SHRI P. C. SETHI: The question is that we make an overall allocation not only to Rajasthan but to other States also. This Government wants the drinking water problem to be solved in the next five years for the whole country. We may do it under A.R.P. or minimum needs programmes, we are also getting World Bank assistance, which is known as International Development Assistance for this purpose also. For example, for Jaipur, we are trying to get five crores as bilateral assistance from Netherlands. So, all possible resources, national and internal are being tried.

SHRI A. T. PATIL: It should be time bound.

SHRI P. C. SETHI: It is going to be time-bound. Even your and my life are also time-bound.

(Interruptions)

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : अध्यक्ष जी, यह विवादास्पद है, आप 20 हजार और 24 हजार की बात छोड़ दीजिए। असल में सवाल यह है कि कितने गांवों को पानी मिला है?

श्री प्रकाश चन्द सेठी : यह तो कुछ ऐसी बात हो गई, जैसे 30 साल में हमने कुछ काम किया ही नहीं है। यह तो आप स्वयं ही समझ सकते हैं कि हमव कितना काम किया है। इसकी डिटेल तो मेरे पास नही है, यदि आप चाहते हैं तो मैं हर प्रांत की डिटेल दे सकता हूं कि कितना काम हुआ है।

AN HON. MEMBER: Please do that.

MR. SPEAKER: It is a too far-fetched request;

श्रीमती संयोगिता राणे : हमारे गांवों में पानी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। मैं गोवा की यूनियन टेरिटरी से आती हूं वहां भी यह समस्या......

MR. SPEAKER: This question relates to Rajasthan only.